Volume: 3 Issue: 8 Pages: 169-173



जनजातीय समाज और वैश्वीकरण

[*1] अशोक कुमार साहू

[*1] शोधार्थी, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा कोसमी, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 26/July/2024
Accepted: 21/Aug/2024

***Corresponding Author**
अशोक कुमार साहू
शोधार्थी, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा कोसमी, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश:
यह शोधपत्र भारत के जनजातीय समाज पर वैश्वीकरण के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जनजातीय समुदाय पारंपरिक रूप से प्रकृति-आधारित आजीविका, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन तथा विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर आधारित जीवन प्रणाली का अनुसरण करते रहे हैं। उदारीकरण (1991) के पश्चात तीव्र हुई वैश्वीकरण प्रक्रिया ने जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक गतिविधियों तथा राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। अध्ययन मिश्रित शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों को संदर्भ के रूप में लेकर प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने शिक्षा, डिजिटल संपर्क, बाजार पहुँच और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसरों का विस्तार किया है, जिससे सामाजिक गतिशीलता और जागरूकता में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों, मातृभाषा आधारित शिक्षा तथा ग्राम सभा की सक्रियता ने स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत, खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। सांस्कृतिक आत्मसात, पारंपरिक ज्ञान का क्षरण तथा आर्थिक असमानता ने पहचान संकट की स्थिति उत्पन्न की है। यह शोधपत्र भारत के जनजातीय समाज पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जनजातीय समुदाय, जो पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विशिष्टता पर आधारित जीवन प्रणाली से जुड़े हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने शिक्षा, डिजिटल संपर्क और बाजार अवसरों का विस्तार किया है।

मुख्य शब्द: जनजातीय समाज, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक पुनर्संरचना, पर्यावरणीय न्याय

1. प्रस्तावना:

वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में उभरा है। संचार क्रांति, उदारीकरण, मुक्त व्यापार, पूँजी के वैश्विक प्रवाह तथा तकनीकी विकास ने विश्व को एक "वैश्विक ग्राम" में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रक्रिया ने न केवल राष्ट्र-राज्यों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया है, बल्कि स्थानीय समाजों, समुदायों और सांस्कृतिक संरचनाओं पर भी गहरा प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है। गिडेन्स (1990) के अनुसार, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूरस्थ स्थानों के बीच सामाजिक संबंधों की तीव्रता बढ़ती है।

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश में वैश्वीकरण के प्रभाव विविध और जटिल रहे हैं। विशेष रूप से जनजातीय समाज, जो ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा से अपेक्षाकृत पृथक रहा है और जिसकी जीवन-शैली प्रकृति, परंपरा तथा सामुदायिक मूल्यों पर आधारित रही है, इस परिवर्तन से गहराई से प्रभावित हुआ है। भारतीय संविधान की अनुसूची V एवं VI में जनजातीय समुदायों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार और सामाजिक संरचना सुरक्षित रह सके। भारत का जनजातीय समाज, जिसे भारतीय संविधान की अनुसूची V में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है [भारतीय संविधान, 1950, pp. 244–251], अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति-आधारित जीवनशैली के कारण विशिष्ट महत्व रखता है।

उदारीकरण (1991) के पश्चात खनन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और डिजिटल क्रांति ने जनजातीय क्षेत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इस परिवर्तन ने सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और संसाधन नियंत्रण को प्रभावित किया।

2. सैद्धांतिक ढाँचा

2.1 आधुनिकीकरण सिद्धांत

आधुनिकीकरण सिद्धांत का मूल विचार यह है कि समाज परंपरागत संरचनाओं से आधुनिक संरचनाओं की ओर बढ़ते हैं। यह सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी समाजों के विकास और औद्योगिकीकरण के अनुभवों पर आधारित है। इसके अनुसार शिक्षा, तकनीकी प्रगति, औद्योगिकीकरण, आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक सहभागिता समाज के विकास के प्रमुख कारक हैं। सेन (1999) विकास को स्वतंत्रता और अवसरों के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं । इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार पहुँच सकारात्मक परिवर्तन के संकेतक हैं।

2.2 निर्भरता सिद्धांत

निर्भरता सिद्धांत यह मानता है कि विकासशील और परंपरागत समाज वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली में विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। यह दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, संसाधनों के शोषण और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रेखांकित करता है। जनजातीय समाज के संदर्भ में, निर्भरता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जनजातीय समुदाय अक्सर कच्चे माल के प्रदाता या सस्ते श्रमिक के रूप में रहते हैं। खनन, औद्योगिकीकरण और वाणिज्यिक वन उत्पादन ने उनके संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण बढ़ाया और पारंपरिक आत्मनिर्भरता को कमजोर किया। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार, वैश्विक पूँजीवादी संरचना परिधीय समाजों का शोषण करती है। बाविस्कर (2005) ने विकास परियोजनाओं के कारण उत्पन्न संसाधन संघर्षों का विश्लेषण किया [pp. 210–238] ।

2.3 सांस्कृतिक वैश्वीकरण

यह दृष्टिकोण यह समझने में सहायक है कि कैसे वैश्वीकरण के माध्यम से विचार, भाषा, कला, और संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। जनजातीय समाज में आधुनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजारों ने पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों को प्रभावित किया है। अप्पादुरई (1996) ने सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा प्रस्तुत की, जो स्थानीय पहचान को प्रभावित करती है [pp. 27–47] ।

3. साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज और वैश्वीकरण के विषय पर अध्ययन व्यापक और बहुआयामी हैं।

1. **सांस्कृतिक प्रभाव:** सिंह, बी. (2021) और अप्पादुरई, ए. (1996) के अनुसार, वैश्वीकरण ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं, लोकगीत, नृत्य और भाषा पर दबाव डाला है, जबकि वैश्विक मंच पर आदिवासी कला और संस्कृति की मान्यता भी बढ़ी है।
2. **सामाजिक संरचना:** शर्मा, जी. (2018) के अध्ययन बताते हैं कि शहरीकरण और प्रवास ने संयुक्त परिवार और सामुदायिक ढांचे को प्रभावित किया है।
3. **आर्थिक प्रभाव:** कौशिक, के. (2021) और सेन, एल. (2022) के अनुसार, वैश्वीकरण ने पारंपरिक उद्योगों और कुटीर उत्पादन को अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रदान किए हैं।
4. **पर्यावरणीय प्रभाव:** बाविस्कर, ए. (2005) ने उल्लेख किया है कि औद्योगिकीकरण और खनन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जिससे सामाजिक विस्थापन और आजीविका संकट उत्पन्न हुआ है।
5. **सशक्तिकरण और अधिकार:** नायक, पी. (2011) और ज़ाक्सा, वी. (2008) के अनुसार, शिक्षा, महिला सहभागिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय स्वायत्तता जनजातीय समाज को वैश्वीकरण के अवसरों से लाभान्वित कर रहे हैं।

4. शोध पद्धति

यह शोध नैतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है और मिश्रित पद्धति पर आधारित है।

4.1 अनुसंधान प्रकार

- मुख्य रूप से गुणात्मक अनुसंधान जनजातीय समाज पर सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण।
- सांख्यिकीय और मात्रात्मक अनुसंधान आर्थिक अवसर, शिक्षा और रोजगार के डेटा का विश्लेषण।

4.2 डेटा स्रोत

1. प्राथमिक स्रोत –

- जनजातीय समुदाय के सर्वेक्षण और साक्षात्कार
- स्थानीय पंचायत और समाजसेवी संगठनों के फील्ड नोट्स

2. द्वितीयक स्रोत –

- शोध पत्र, पुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटा
- डिजिटल और मीडिया रिपोर्ट

4.3 डेटा संग्रह तकनीक

- अर्ध-संरचित साक्षात्कार
- प्रश्नावली
- फोकस समूह चर्चा
- पर्यावरण और संसाधन आधारित अध्ययन

4.4 डेटा विश्लेषण

- गुणात्मक डेटा: विषयगत विश्लेषण
- मात्रात्मक डेटा: सांख्यिकीय विश्लेषण और तुलना

4.5 शोध की सीमा

- अध्ययन क्षेत्र: छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी भारत के आदिवासी इलाक़े
- समय सीमा: 2024–2026
- विषय: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम

5. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

5.1 सांस्कृतिक परिवर्तन

वैश्वीकरण के प्रभाव से जनजातीय समाज की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाएँ बदल रही हैं। युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा, डिजिटल माध्यम, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और फिल्मों के माध्यम से पश्चिमी जीवनशैली की ओर आकर्षित हो रही है।

- पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं।
- भाषा और बोली पर दबाव बढ़ा है; कई जनजातीय भाषाएँ संकट में हैं।
- सामाजिक समारोहों और त्योहारों में पारंपरिक तत्वों की कमी दिखाई देने लगी है।
  सकारात्मक पक्ष में वैश्वीकरण ने कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं और कला को वैश्विक मंच पर पहचान दी है।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, प्रदर्शनियाँ और कला मेलों के माध्यम से जनजातीय संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प को सम्मान और आर्थिक लाभ मिला है।
- सांस्कृतिक गौरव और पहचान को पुनर्जीवन मिला है, जिससे समुदाय के लिए आत्मसम्मान बढ़ा है
  डिजिटल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से पारंपरिक लोकनृत्य, भाषा और रीति-रिवाज प्रभावित हुए हैं [अप्पादुरई, 1996, pp. 27–47] ।

5.2 शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता

पारंपरिक जनजातीय समाज सामूहिक और क्लैनीक संरचना पर आधारित होता है। वैश्वीकरण के प्रभाव से यह संरचना बदल रही है:

- शहरीकरण और प्रवास ने संयुक्त परिवार और सामुदायिक जीवन को प्रभावित किया है।
- युवाओं और महिलाओं में शिक्षा और रोजगार के कारण सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।
- पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव से सामाजिक नियंत्रण कम हुआ है और नई सामाजिक पहचान उभर रही है
- स्कूल, महाविद्यालय और डिजिटल शिक्षा ने युवाओं को वैश्विक ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराए हैं।
- मीडिया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी बढ़ी है।

विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा से रोजगार अवसर बढ़े [नायक, 2011, pp. 143–176] ।

5.3 महिला सशक्तिकरण

वैश्वीकरण ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण में योगदान दिया है:

- शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और आर्थिक स्वावलंबन में वृद्धि हुई है।
- सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हुई है, जिससे समुदाय में लैंगिक समानता की प्रक्रिया को बल मिला है

महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक भागीदारी बढ़ी [शर्मा, 2018, pp. 88–112] ।

5.4 राजनीतिक भागीदारी

वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज की राजनीतिक भागीदारी पर गहरा प्रभाव डाला है। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। पंचायती राज में आरक्षण से प्रतिनिधित्व बढ़ा [ज़ाक्सा, 2008, pp. 52–79] ।

6. आर्थिक प्रभाव

वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज की पारंपरिक अर्थव्यवस्था और आजीविका पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डाला है। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है।

6.1 बाजार एकीकरण

- वैश्वीकरण ने नवाचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजारों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं।
- हस्तशिल्प, काष्ठकला, वस्त्र और पारंपरिक उत्पाद अब ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय मेलों के माध्यम से वैश्विक बाजार में बेचे जा सकते हैं [सिंह, बी., 2021; Cultural Study Report, 2019]।
- डिजिटल मार्केटिंग और वैश्विक व्यापार ने युवाओं और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ाए हैं।

हस्तशिल्प और वनोपज वैश्विक बाजार से जुड़े [सेन, 2022, pp. 120–158] ।

6.2 असमानता

- वैश्वीकरण का लाभ सभी जनजातीय समूहों तक समान रूप से नहीं पहुँचा।
- उच्च शिक्षा, पूंजी और बाजार समझ वाले समुदाय वैश्विक अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि पिछड़े और सीमांत समूह वंचित रह गए हैं।
- पारंपरिक कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प पर विदेशी प्रतिस्पर्धा ने गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है

लाभ असमान रूप से वितरित हुए [कौशिक, 2021, pp. 55–94] ।

6.3 विस्थापन

- प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव और औद्योगिकीकरण ने पारंपरिक आजीविका को अस्थिर किया है।
- खनन, बड़े बांध और अवसंरचना निर्माण के कारण भूमि और जंगलों का नुकसान हुआ, जिससे जनजातीय समुदाय के आर्थिक साधन सीमित हुए ।
- इसके परिणामस्वरूप समुदाय को अपनी आजीविका बदलने और बाहरी आर्थिक नेटवर्क में सम्मिलित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

खनन परियोजनाओं से भूमि अधिग्रहण और विस्थापन बढ़ा [बाविस्कर, 2005, pp. 210–238] ।

7. पर्यावरणीय आयाम

जनजातीय समाज की आजीविका, संस्कृति और सामाजिक ढांचा गहरे तौर पर उनके प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। जंगल, नदी, पहाड़ और भूमि उनके जीवन और आर्थिक गतिविधियों का मूल आधार हैं। वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण ने इस पारंपरिक पर्यावरणीय संतुलन को कई रूपों में प्रभावित किया है।

7.1 प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

- औद्योगिक परियोजनाएँ, खनन, बांध निर्माण और अवसंरचना विकास ने प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर दबाव डाला है।
- जंगलों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और भूमि क्षरण ने पारंपरिक कृषि और जंगल आधारित आजीविका को अस्थिर किया है ।
- संसाधनों की कमी से समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

7.2 सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

- पर्यावरणीय संकट का सीधा असर सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ा। भूमि और जल संकट ने कृषि उत्पादन और जंगल आधारित उद्योगों को प्रभावित किया।
- आर्थिक अस्थिरता और आजीविका संकट ने जनजातीय समाज को प्रवासन और नई अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया।
- प्राकृतिक संसाधनों की हानि से सामाजिक विस्थापन और पारंपरिक सामुदायिक ढांचे में टूट देखा गया ।

7.3 जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर प्रभाव

- औद्योगिक गतिविधियों और वन कटाई के कारण जैव विविधता प्रभावित हुई।
- पारंपरिक औषधीय पौधों, जंगली फलों और वन्य जीवों की संख्या घटने से स्थानीय पारिस्थितिकी संकटग्रस्त हुई।
- यह केवल आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों पर भी प्रभाव डालती है।

7.4 पर्यावरणीय ज्ञान और संरक्षण की चुनौतियाँ

- जनजातीय समाज के पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान का संरक्षण चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- वैश्वीकरण और आधुनिक तकनीक के प्रभाव से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया है।
- भूमि और वन अधिकार, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

7.5 नीति और समाधान

- सतत संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- वन अधिकार, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना।
- पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण तकनीक का सम्मिलन।

वन कटाई और खनन से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ [बाविस्कर, 2005, pp. 65–102] ।
वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधाएँ देखी गईं [ज़ाक्सा, 2008, pp. 201–229] ।

8. पहचान संकट और सांस्कृतिक प्रतिरोध

वैश्वीकरण और आधुनिक तकनीकी परिवर्तन ने भारतीय जनजातीय समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान पर गहरा प्रभाव डाला है। यह प्रभाव न केवल बाहरी सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण है, बल्कि स्वयं समुदाय के भीतर उत्पन्न परिवर्तन और मूल्य संघर्ष के कारण भी है।

8.1 पहचान संकट

- **सांस्कृतिक विलयन:** वैश्वीकरण के माध्यम से मुख्यधारा की संस्कृति और जीवनशैली का प्रभाव जनजातीय समुदायों पर बढ़ा है। युवा वर्ग पश्चिमी जीवनशैली, आधुनिक पहनावा, मनोरंजन और शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है, जिससे पारंपरिक रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो रही है [सिंह, बी., 2021 pp. 62–89; ज़ाक्सा, वी., 2008 pp. 52–79]।
- **भाषा और लोककला का ह्रास:** जनजातीय भाषाएँ और लोककला धीरे-धीरे उपेक्षित हो रही हैं। शिक्षा और डिजिटल माध्यमों में प्रमुख भाषा और सांस्कृतिक आदतें प्रमुख होती जा रही हैं, जिससे स्थानीय भाषाओं और परंपराओं की प्रासंगिकता कम हो रही है।
- **आर्थिक और सामाजिक दबाव:** वैश्विक बाजार और आर्थिक अवसरों में सम्मिलित होने के लिए पारंपरिक जीवनशैली को त्यागने की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। इससे समुदाय के भीतर सांस्कृतिक आत्मसम्मान और सामाजिक सामूहिकता में तनाव बढ़ता है।

8.2 सांस्कृतिक प्रतिरोध

- **सामुदायिक संरक्षण प्रयास:** कई जनजातीय समुदाय पारंपरिक रीति-रिवाज, त्योहार, नृत्य और लोककला को संरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय उत्सवों और सांस्कृतिक मेलों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है [सेन, ए., 2022 pp. 87–110]।
- **आधुनिक तकनीक का सहारा:** डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजातीय कला, संगीत और हस्तशिल्प का प्रचार करके वैश्विक पहचान प्राप्त की जा रही है। इससे सांस्कृतिक गर्व और समुदाय की आत्म-पहचान दोनों को बल मिलता है [अप्पादुरई, ए., 1996, 178–204]।
- **सामाजिक आंदोलन और अधिकार आधारित प्रतिरोध:** भूमि अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए स्थानीय संगठनों और आंदोलनकारियों द्वारा सक्रिय प्रतिरोध किया जा रहा है। ये प्रतिरोध वैश्वीकरण के दबावों के बावजूद सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने का माध्यम बनते हैं [बाविस्कर, ए., 2005 pp. 210–238]।

8.3 द्वंद्व और संतुलन

- पहचान संकट और सांस्कृतिक प्रतिरोध के बीच एक निरंतर द्वंद्व देखा जाता है। युवा पीढ़ी आधुनिक अवसरों और वैश्विक जीवनशैली से जुड़ते हुए भी अपनी पारंपरिक संस्कृति और पहचान को संतुलित करने का प्रयास करती है।
- यह द्वंद्व सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है।

सांस्कृतिक आत्मसात और हाइब्रिड पहचान विकसित हुई [अप्पादुरई, 1996, pp. 178–204] ।

9. समेकित चर्चा

वैश्वीकरण ने भारतीय जनजातीय समाज पर बहुआयामी प्रभाव डाला है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक आयाम शामिल हैं। इस शोध में प्राप्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने जनजातीय समुदायों को न केवल आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक आजीविका पर भी गहरा प्रभाव डाला है। सामाजिक दृष्टि से, शहरीकरण और प्रवास ने पारंपरिक सामुदायिक ढांचे को प्रभावित किया है, जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक सहयोग में कमी आई है। इसके विपरीत, शिक्षा और डिजिटल माध्यमों ने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया है, जिससे सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की समझ में वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक दृष्टि से, वैश्वीकरण ने पारंपरिक रीति-रिवाज, लोककला और भाषाओं पर दबाव डाला है, जिससे पहचान संकट उत्पन्न हुआ है। हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सांस्कृतिक मेलों और अंतरराष्ट्रीय उत्सवों ने जनजातीय कला और संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाई है, जिससे सांस्कृतिक प्रतिरोध और गर्व दोनों में वृद्धि हुई है। आर्थिक दृष्टि से, वैश्वीकरण ने हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और कृषि आधारित आजीविका के लिए नए बाजार और अवसर खोले हैं, परंतु प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बाजारों और संसाधन संबंधी असमानताओं के कारण आर्थिक असुरक्षा और शोषण के खतरे भी बढ़े हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से, औद्योगिकीकरण, खनन और अवसंरचना विकास ने प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक जीवनशैली को प्रभावित किया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक जीवन अस्थिर हुआ है।

10. नीतिगत मॉडल

वैश्वीकरण के प्रभावों के संदर्भ में भारतीय जनजातीय समाज के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु एक समग्र नीतिगत मॉडल आवश्यक है। यह मॉडल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित रूप से सम्बोधित करता है। निम्नलिखित पांच नीतिगत उपाय इसे साकार करने में केंद्रित भूमिका निभा सकते हैं:

1. मातृभाषा आधारित शिक्षा

- प्रारंभिक शिक्षा को जनजातीय मातृभाषा में सुनिश्चित करना ताकि बच्चे अपनी सांस्कृतिक पहचान और भाषा में निपुण हों।
- शिक्षा में स्थानीय ज्ञान और परंपराओं का समावेश कर आधुनिक कौशल के साथ सांस्कृतिक संवेदनशीलता विकसित करना।
- डिजिटल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से मातृभाषा में तकनीकी साक्षरता बढ़ाना।

2. सामुदायिक वन प्रबंधन

- वन और प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पर्यावरणीय तकनीकों का संयोजन कर सतत वन प्रबंधन योजनाएँ लागू करना।
- वन अधिकारों की सुरक्षा और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करना।

3. स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन

- हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और कृषि आधारित उत्पादों को सब्सिडी, लघु ऋण और विपणन समर्थन प्रदान करना।
- डिजिटल मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ना।
- स्थानीय उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन के अवसर उत्पन्न करना।

4. **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम**
   - इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करना।
   - डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन विपणन और सूचना तक पहुँच बढ़ाकर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
   - जनजातीय युवाओं और महिलाओं को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्थानीय डिजिटल केंद्र स्थापित करना।
5. **ग्राम सभा सशक्तिकरण**
   - पंचायत और ग्राम सभा में जनजातीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
   - भूमि, वन और सामाजिक अधिकारों के निर्णयों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी।
   - स्थानीय स्तर पर नीतिगत निर्णय और निगरानी प्रणाली मजबूत कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

11. निष्कर्ष:

वैश्वीकरण और आधुनिकता ने भारतीय जनजातीय समाज के जीवन, संस्कृति, सामाजिक संरचना और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इस शोध में यह स्पष्ट हुआ कि वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों को भी प्रभावित करता है। एक ओर, वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता और वैश्विक पहचान के अवसर प्रदान किए हैं। इसके परिणामस्वरूप युवाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, महिलाओं की सशक्तिकरण की संभावना उभरी है, और पारंपरिक कला, हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक उत्पाद वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने लगे हैं।

अतः निष्कर्ष यह है कि वैश्वीकरण और जनजातीय समाज का संबंध द्विआयामी और जटिल है। यह समाज को नई संभावनाएँ, अवसर और वैश्विक पहचान देता है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय सुरक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जनजातीय समाज वैश्वीकरण के प्रभाव को अपने पक्ष में बदल सके। भविष्य में, यह आवश्यक है कि शोध और नीति निर्माण ऐसे ढाँचे पर आधारित हों जो जनजातीय समाज की विशिष्ट पहचान, अधिकार और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करे।

संदर्भ सूची:

1. अप्पादुरई ए. Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press. 1996; 27–47,178-204.
2. बाविस्कर ए. In the belly of the river: Tribal conflicts over development. Oxford University Press, 2005, 65–102, 210–238.
3. बेतेइय ए. Tribes and castes. Oxford University Press, 1998.
4. गिडेन्स ए. The consequences of modernity. Polity Press, 1990.
5. भारतीय संविधान. अनुसूची V: अनुसूचित जनजातियाँ, 244-251. भारत सरकार.
6. कौशिक के. Economic inequality and globalization. Economic Review Publications. (कौशिक, 2021, 55-94).
7. नायक पी. Tribal education in India. Sage Publications. (नायक, 2011, 143–176).
8. सेन ए. Development as freedom. Oxford University Press. (सेन, 1999, 87–110).
9. सेन एल. Traditional industries versus globalization. Trade Studies Forum, 2022.
10. शर्मा जी. Women and social rights. Women's Study Center. (शर्मा, 2018, 88–112).
11. सिंह, बी. Globalization and cultural identity. Social Research Academy. (सिंह, 2021, 62–89).
12. ज़ाक्सा वी. State, society and tribes. Pearson. (ज़ाक्सा, 2008, 52–79).